श्रावण मास, कृष्ण पक्ष 1 वर्ष, अंक 148, पृष्ठ 4, मूल्य 1.00

अखण्ड भारत सन्देश

www.akhandbharatsandesh.net

प्रयागराज से प्रकाशित

नगर संस्करण प्रयागराज रविवार, 3 जनवरी, 2021

विश्व निर्माण एवं मानव विकास को द्रुतगति प्रदान करने हेतु क्रियायोग आश्रम एवं अनुसंधान संस्थान की एक अनुपम भेंट

मांगें नहीं मानी गईं तो ट्रैक्टर के साथ निकालेंगे 'किसान गणतंत्र परेड'

कल होगी वार्ता, सरकार पर बढ़ाया दबाव

किसान मोर्चा ने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे मकर संक्रांति पर 13 जनवरी को देशभर में तीनों कानूनों की होली जलाएंगे। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर के साथ अपनी अलग किसान गणतंत्र परेड निकालेंगे।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कृषि सुधार कानूनों को लेकर चार जनवरी को प्रस्तावित वार्ता से पहले केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसान संगठनों ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे मकर संक्रांति पर 13 जनवरी को देशभर में तीनों कानूनों की होली जलाएंगे। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर के साथ अपनी अलग 'किसान गणतंत्र परेड' निकालेंगे। उस दिन दिल्ली के बार्डर पर उनके धरने के दो माह हो जाएंगे।

प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में किसान नेताओं ने बताया कि इस परेड के लिए अभी जगह तय नहीं हुई है। हालांकि इतना जरूर है कि इसके जरिये राजपथ के गणतंत्र दिवस परेड में व्यवधान डालने की कोशिश नहीं होगी।

संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय समन्वय समिति के सदस्य बलबीर सिंह राजे वाल, दर्शन पाल, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जगजीत सिंह डल्लेवाल और योगेंद्र यादव ने बताया कि चार जनवरी को वार्ता विफल होने की स्थिति में छह जनवरी को केएमपी (कुंडली-मानेसर-पलवल) एक्सप्रेस-वे पर ट्रैक्टर मार्च के जरिये शक्ति प्रदर्शन होगा। शाहजहांपुर पर मोर्चा लगाए किसान दिल्ली कूच करेंगे। वहीं छह से 20 जनवरी तक केंद्र सरकार के खिलाफ देशभर में 'जागृति पखवाड़ा' मनाया जाएगा। 23 जनवरी को सभी राज्यों की राजधानियों में राज्यपाल के निवास के बाहर किसान आंदोलन समर्थक डेरा डालेंगे। किसान नेताओं ने केंद्र सरकार के आधे मसले हल होने संबंधी दावे के विपरीत कहा कि अभी मुख्य मांगों पर गतिरोध बरकरार है। स्थिति 'पूंछ निकलने और हाथी के फंसे रहने' वाली है। कृषि संबंधी तीनों कानून को वापस लेने तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी-निजी खरीद की गारंटी पर अब भी सरकार टस से मस नहीं है। नेताओं ने दावा किया कि 30 दिसंबर की वार्ता में दो छोटे मुद्दों पर सरकार की ओर से सहमति का अब तक लिखित प्रस्ताव भी नहीं मिला है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, सभी सुरक्षा पहलुओं पर समान ध्यान देने की कोशिश

नई दिल्ली, आइएएनएस। राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं पर समान रूप से ध्यान देने की गंभीरता से कोशिश कर रही है।

'नेशनल पुलिस के-9' जर्नल का पहला अंक जारी करते हुए शाह ने यह बात कही। पुलिस सर्विस के-9 या पुलिस डॉग्स पर देश में यह पहला ऐसा प्रकाशन है। गृह मंत्री ने कहा कि पुलिस डाग स्क्वायड समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करने में फोर्स के सहायक के तौर पर कार्य कर सकता है जिस तरह देश में ड्रोन या सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा कि डॉग्स का इस्तेमाल ड्रग्स का पता लगाने या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में प्रभावी तरीके से किया जा सकता है। बता दें कि गृह मंत्रालय के पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग के तहत नवंबर, 2019 में विशेष पुलिस के9 प्रकोष्ठ की स्थापना की गई थी। पुलिस के-9 जर्नल में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में सेक्शन हैं और इसे हर साल अप्रैल और अक्टूबर में जारी किया जाएगा।

इस समारोह में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के महानिदेशक और बलों के वरिष्ठ रैंकिंग पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया था। जबकि देश भर के सीएपीएफ कर्मियों ने वर्चुअल के माध्यम से भाग लिया।

इस दौरान सुरक्षा कर्मियों के अलावा कुछ प्रतिष्ठित विदेशी विशेषज्ञों ने भी उद्घाटन मुद्दे पर अपने लेखों में योगदान दिया है।

21 साल से कम वाले नहीं पी पाएंगे सिगरेट, सरकार उठाने जा रही कदम

नई दिल्ली, आइएएनएस। धूमपान एवं तंबाकू उत्पादों के सेवन को हतोत्साहित करने की दिशा में अहम कदम उठाने की तैयारी है। सरकार ने सिगरेट एवं तंबाकू उत्पाद खरीदने की न्यूनतम उम्र सीमा बढ़ाकर 21 साल करने का प्रस्ताव रखा है। अभी यह उम्र 18 साल है। इस दिशा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन निषेध और व्यापार व वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण नियमन) संशोधन कानून, 2020 का मसौदा पेश किया है।

प्रस्तावित संशोधन के मुताबिक, ऐसे किसी व्यक्ति को सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जाएंगे, जिसकी उम्र 21 साल से कम हो। शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर की परिधि में भी इन उत्पादों की बिक्री पर रोक रहेगी। इस संशोधन विधेयक में यह भी कहा गया है कि सिगरेट या कोई भी तंबाकू उत्पाद ऑरिजिनल पैकिंग में ही बेचा जाएगा। यानी सिगरेट या तंबाकू उत्पाद की पैकिंग खोलकर फुटकर में बेचने की अनुमति नहीं होगी। नियमों के उल्लंघन पर दो साल की जेल और एक लाख रुपये तक का जुमार्ना हो सकता है। दूसरी बार ऐसा करने पर पांच साल तक की जेल और पांच लाख रुपये तक के जुमार्ने का प्रावधान है। प्रतिबंधित क्षेत्र में धूमपान करने पर जुमार्ने को 200 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये करने का प्रस्ताव है। संशोधन विधेयक में सिगरेट एवं तंबाकू

धूमपान एवं तंबाकू उत्पादों के सेवन को हतोत्साहित करने की दिशा में अहम कदम उठाने की तैयारी है। सरकार ने सिगरेट एवं तंबाकू उत्पाद खरीदने की न्यूनतम उम्र सीमा बढ़ाकर 21 साल करने का प्रस्ताव रखा है। अभी यह उम्र 18 साल है।

उत्पादों के अवैध कारोबार पर भी निशाना साधा गया है। इसमें अवैध उत्पाद बिक्री पर एक साल की जेल और 50 हजार रुपये तक के जुमार्ने का प्रावधान है। दूसरी बार ऐसा करने पर दो साल तक की जेल और एक लाख रुपये तक का जुमार्ना हो सकता है। गैरकानूनी तरीके से सिगरेट बनाने पर दो साल की जेल और एक लाख रुपये तक का जुमार्ना होगा।

विज्ञापन को लेकर इसमें कहा गया है, 'कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी माध्यम से सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन नहीं करेगा, न ही किसी रूप में इन उत्पादों के सेवन को प्रोत्साहित करने वाली गतिविधि या किसी विज्ञापन का हिस्सा बनेगा।'

टावर तोड़फोड़ मामले में जियो व एयरटेल में ठनी

नई दिल्ली, पीटीआइ। मुकेश अंबानी नियंत्रित टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो के टेलीकॉम टावर क्षतिग्रस्त कर दिए जाने के मामले में कंपनी और उसकी स्पर्धी एयरटेल में ठन गई है। भारती एयरटेल ने दूरसंचार विभाग (डीओटी) को पत्र लिखकर जियो के आरोपों को बेबुनियाद और साख पर चोट पहुंचाने वाला बताया है। टेलीकॉम सचिव अंशु प्रकाश को लिखे पत्र में एयरटेल ने कहा कि वह रिलायंस जियो द्वारा 28 अप्रैल, 2020 को डीओटी को लिखे पत्र से अवगत है। इस पत्र में जियो ने पंजाब व हरियाणा में चल रहे किसान आंदोलनों के दौरान उसके टेलीकॉम टावर क्षतिग्रस्त होने की बात कही है। एयरटेल का कहना था कि रिलायंस जियो के आरोप बेबुनियाद हैं, क्योंकि उसने इसका कोई सुबूत नहीं दिया है कि उसके टेलीकॉम टावरों को क्षतिग्रस्त

करने वालों को एयरटेल ने उकसाया है। गौरतलब है कि वर्तमान किसान आंदोलन के दौरान पंजाब व हरियाणा में रिलायंस जियो के करीब 1,600 टेलीकॉम टावरों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। आंदोलन के दौरान किसानों की तरफ से लगातार यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार अंबानी और अडानी समेत चुनिंदा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए नया कृषि कानून लेकर आई है। रिलायंस जियो ने दिसंबर में पहले टेलीकॉम नियामक ट्राई और बाद में डीओटी को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि पंजाब व हरियाणा में उसके टेलीकॉम टावरों को जिन लोगों ने क्षतिग्रस्त किया है, उन्हें ऐसा करने के लिए एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी स्पर्धी कंपनियां उकसा रही हैं।रिलायंस जियो का यह भी आरोप था कि ये कंपनियां जियो के ग्राहकों को अपने नेटवर्क पर लाने की कोशिशों के तहत ऐसा कर रही हैं। भारती एयरटेल के मुख्य नियामक अधिकारी राहुल वत्स ने डीओटी को 28 दिसंबर, 2020 को लिखे पत्र में कहा कि जियो के टेलीकॉम टावरों को क्षतिग्रस्त करने के लिए एयरटेल द्वारा लोगों को उकसाने के आरोप बेबुनियाद और बेतुके हैं। जियो अब तक इसका कोई सुबूत नहीं दे पाई है।

एमपी में बर्ड फ्लू की दस्तक, मृत मिले कौओं में बर्ड फ्लू बीमारी की पुष्टि

भोपाल, स्टेट ब्यूरो। मध्य प्रदेश के इंदौर के रेसीडेंसी इलाके में मृत मिले कौओं में बर्ड फ्लू बीमारी की पुष्टि हुई है। इसे देखते हुए वन विभाग ने प्रदेश के सभी संरक्षित क्षेत्रों (अभयारण्य और नेशनल पार्क) के प्रबंधन को सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं। उनके प्रबंधन से कहा गया है कि क्षेत्र के सभी जलाशय की लगातार निगरानी करें और किसी भी पक्षी में बर्ड फ्लू के लक्षण दिखाई देने पर स्थानीय पशु चिकित्सकों की मदद से सैंपल लेकर जांच के लिए भेजें।

राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दी है। पिछले दिनों इंदौर में मृत मिले कौओं में बर्ड फ्लू के वायरस (एच-5, एन-8) की पुष्टि हुई है। पशु चिकित्सा विभाग ने राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान, भोपाल से कौओं के शव का परीक्षण कराया था। इसकी रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद पशुपालन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसी कड़ी में वन विभाग ने संरक्षित क्षेत्रों के संचालकों को निगरानी बढ़ाने को कहा है। वहीं संचालक पशुपालन ने सभी संयुक्त संचालक और उप संचालक को भी निगरानी बढ़ाने को कहा है।

पिछले नौ माह से कोरोना महामारी से जूझ रहे राजस्थान में अब बर्ड फ्लू का खतरा हो गया है। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए राजस्थान के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व और अन्य इलाकों में बर्ड फ्लू को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। दरअसल, पिछले एक सप्ताह में प्रदेश के विभिन्न इलाकों में करीब 400 कौओं की मौत को देखते हुए वन, पशुपालन और चिकित्सा विभाग सतर्क हुआ है। सरकार ने जिला कलेक्टरों को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश के जोधपुर जिले में सबसे अधिक करीब 200 कौओं की मौत अब तक हो चुकी है। वहीं, झालावाड़ में 80, बारां में 70, कोटा में

30 कौओं की मौत की बात सामने आई है। सवाईमाधोपुर, नागौर व टोंक जिलों में भी कुछ कौओं की मौत हुई है। नागौर में करीब पांच दर्जन मोर की मौत भी हुई है। इनकी मौत जहरीला पदार्थ खाने से होने की बात सामने आई है। कौओं की मौत के बाद पशुपालन विभाग की टीम ने अलग-अलग स्थानों से सैंपल लिए हैं। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन एमएल मीणा की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि प्रदेश में बर्ड फ्लू के वायरस मिले हैं। इसे रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। टाइगर रिजर्व के लिए यह सबसे खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने वैटलेंड्स पर भी निगरानी रखने के लिए कहा है। प्रदेश की पशुपालन सचिव आरूषी मलिक ने इस संबंध में जिला स्तर के अधिकारियों को सजग रहने के लिए कहा है।

इधर, अजमेर संभाग के नागौर जिले में मकराना उपखंड के ग्राम कालवा बड़ा में शुक्रवार को किसी जहरीले पदार्थ के खाने से 52 मोरों सहित कई छोटे पक्षी मर गए। मौके पर पहुंची चिकित्सा विभाग की टीम लगभग 50 मोर का उपचार कर उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। वहीं, दो टीम बना कर मृत मोर का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। कुचामन से डीडीएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। कालवा बड़ा के सरपंच दिलीप सिंह ने बताया कि सुबह घर से बाहर आने पर एक बरगद के पेड़ नीचे काफी संख्या में मोर मृत मिले, जिसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दी गई। सूचना पर नायब तहसीलदार गजेंद्र सिंह मय टीम मौके पर पहुंचे।

टीकाकरण के लिए देश तैयार, भारत बायोटेक के स्वदेशी टीके के आपात इस्तेमाल को भी एक्सपर्ट पैनल की मंजूरी

कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में देश को दूसरी बड़ी सौगात मिली। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की कोरोना पर विषय विशेषज्ञ समिति ने भारत बायोटेक के स्वदेशी कोविड वैक्सीन कोवाक्सिन के आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी दिए जाने की सिफारिश कर दी है।

नीलू रंजन, नई दिल्ली। कोरोना से जंग के बीच देश को दो दिन में दूसरा हथियार मिल गया है। शुक्रवार को सीरम इंस्टीट्यूट के टीके कोविशील्ड के बाद शनिवार को विशेषज्ञों की समिति (सीईसी) ने पहले स्वदेशी टीके कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत देने की अनुसंशा कर दी है। इस वैक्सीन को भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आइसीएमआर) ने विकसित किया है। वहीं, कोविशील्ड को आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी-एस्ट्राजेनेका ने विकसित किया है और सीरम इंस्टीट्यूट भारत में इसका उत्पादन कर रहा है।

माना जा रहा है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआइ) जल्द ही दोनों वैक्सीन पर सीईसी की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए इनके इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए हरी झंडी दिखा सकता है। इस बीच, सीरम इंस्टीट्यूट के टीके की तैयार डोज की गुणवत्ता जांचने का काम भी हो गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ने 31 दिसंबर तक 7.5 करोड़ डोज तैयार होने और जनवरी के पहले हफ्ते तक इसे बढ़ाकर 10 करोड़ करने का दावा किया है। इनमें लगभग 20 बैच में रखे गए पांच करोड़ सैंपल की गुणवत्ता की जांच हिमाचल प्रदेश के कसौली स्थित सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी में की गई। इन्हें लोगों को लगाए जाने के लिए सही पाया गया है। जाहिर है कि डीसीजीआइ की हरी झंडी मिलते ही इन पांच करोड़ वैक्सीन डोज को लोगों को लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। भारत बायोटेक ने अभी तक कोवैक्सीन की तैयार डोज की जानकारी नहीं दी है।

सूत्रों के अनुसार जिन पांच करोड़ डोज पर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी की मुहर लगी है, उनमें से तीन करोड़ डोज सीधे तौर पर भारत को मिलेंगी। दो करोड़ डोज विश्व स्वास्थ्य संगठन को दी जानी है, जिनमें से एक करोड़ डोज विश्व स्वास्थ्य संगठन अपनी ओर से भारत को मुफ्त में देगा। इस तरह भारत के लिए चार करोड़ डोज बिल्कुल तैयार हैं।

भारत बायोटेक को लेकर उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि हैदराबाद की कंपनी की ओर से उपलब्ध कराए गए ट्रायल के अतिरिक्त डाटा का विश्लेषण करने के बाद इसे इस्तेमाल के लिए सुरक्षित पाया गया। कोवैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल अभी जारी है। पहले और दूसरे फेज के ट्रायल में इस वैक्सीन को पूरी तरह सुरक्षित और कोरोना संक्रमण को रोकने में सफल पाया गया था। इसी के आधार पर इसके इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत देने का फैसला किया गया।

जानकारों का कहना है कि ब्रिटेन में सामने आए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को देखते हुए स्वदेशी टीका कोवैक्सीन ज्यादा कारगर हो सकता है। इस टीके को लाइव वायरस को कल्चर करने के बाद उन्हें निष्क्रिय कर तैयार किया गया है। यह वैक्सीन निर्माण की सबसे पुरानी तकनीक है। यह वैक्सीन कोरोना के पूरे वायरस के लिए शरीर में प्रतिरोधक एंटीबॉडी तैयार करती है। वहीं फाइजर, मॉडर्ना, स्पुतनिक और कोविशील्ड को अत्याधुनिक तकनीक से कोरोना वायरस के सिर्फ स्पाइक प्रोटीन को टारगेट करने के लिए तैयार किया गया है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि डीसीजीआइ की अनुमति मिलते ही वैक्सीन को देश के छह स्थानों पर बनाए गए रीजनल सेंटर भेजने का काम शुरू हो जाएगा। वहां से राज्यों की राजधानियों और फिर जिला स्तर पर तैयार कोल्ड स्टोरेज तक पहुंचाया जाएगा। टीकाकरण की पूरी सप्लाई चेन तैयार है।

इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोविड वैक्सीन के सुरक्षित और प्रभावी होने को लेकर अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं से लोगों को गुमराह नहीं होने की अपील की। उन्होंने कहा कि वैक्सीन को मंजूरी देने से पहले सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा और अप्रूवल में सुरक्षा मानकों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

चीन का मुकाबला करने के लिए जापान बनाएगा चालक रहित लड़ाकू विमान

नई दिल्ली, आइएएनएस। चीन की सामरिक क्षमता का मुकाबला करने के लिए जापान रिमोट कंट्रोल से संचालित लड़ाकू विमानों को विकसित कर रहा है। जापान की यह योजना 15 वर्षों की है। उसका लक्ष्य 2035 तक रिमोट संचालित लड़ाकू विमानों को तैनात करने का है।

जापान चीन की सामरिक क्षमता से आगे निकलने की योजना बना रहा है। चीन के पास इस समय एक हजार से ज्यादा लड़ाकू विमान हैं। इनमें सुपसोनिक विमानों की संख्या जापान से तीन गुना ज्यादा है।

जापान पांचवी जनरेशन के राडार से बचने वाले लड़ाकू विमान भी विकसित कर रहा है। रक्षा मंत्रालय तीन तरह से ड्रोन विकसित कर रहा है। पहले जो केवल रिमोट से संचालित होते हैं। दूसरे एक चालक वाले विमान, जिससे एक साथ कई ड्रोन संचालित किए जा सकेंगे। तीसरे सभी तरह से स्वाचालित और मानव रहित होंगे। इन सभी को पूरी तरह से विकसित करने का समय जापान ने 2035 तक का तय किया है। जापान की तीन बड़ी कंपनियों को इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चीन के संभावित खतरे को देखते हुए ही जापान हिंद-प्रशांत क्षेत्र में क्वाड का सदस्य बना है। यहां इसके सहयोगी भारत, अमेरिका और आस्ट्रेलिया हैं।

सीडीएस जनरल रावत ने अरुणाचल में अग्रिम सैन्य ठिकानों का दौरा किया

नई दिल्ली, एजेंसियां। चीफ आफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत ने शनिवार को अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के नजदीक वायुसेना के कई ठिकानों का दौरा कर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जवानों का बुलंद हौसला देखकर यकीन होता है कि भारतीय सेना से मुकाबला करने वाले टूटकर बर्बाद हो जाएंगे। पूर्वी लद्दाख में पिछले आठ महीनों से चीन के साथ जारी सीमा विवाद के कारण भारतीय सेनाएं सीमाओं पर काफी चौकसी बरत रही हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जनरल रावत ने कुछ इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और वरिष्ठ सैन्य कमांडरों ने उन्हें क्षेत्र के सुरक्षा हालात के अहम पहलुओं की जानकारी दी। सीडीएस ने अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी और लोहित सेक्टर में अग्रिम चौकियों पर तैनात स्पेशल फ्रंटियर फोर्स (एसएफएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आइटीबीपी) और सेना के जवानों के साथ मुलाकात कर उनका हौसला भी बढ़ाया। उन्होंने जवानों को क्षेत्र में उनकी युद्ध तैयारी और सतत निगरानी के लिए बधाई भी दी।

देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने अपने नए कार्यालय का एक साल पूरा होने पर अरुणाचल प्रदेश और असम में चीन की सीमा के पास भारतीय सैन्य ठिकानों का दौरा किया।

बातचीत में जनरल रावत ने कहा कि कोई ताकत भारतीय सैन्य बलों को उनके कर्तव्यों से नहीं डिगा सकती। प्रभावी निगरानी बनाए रखने और आपरेशनल तैयारियों को बढ़ाने में नए तरीके अपनाने के लिए सीडीएस ने सैनिकों को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि ऐसे चुनौतीपूर्ण हालात में सिर्फ भारतीय सैनिक ही सतर्क रह सकते हैं और सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। बता दें कि जनरल रावत ने शुक्रवार को देश के पहले सीडीएस के तौर पर एक साल पूरा किया है।

सूत्रों के अनुसार, जनरल रावत रविवार को भी कई अन्य अग्रिम ठिकानों का दौरा कर सामरिक तैयारियों और सुरक्षा हालात का जायजा लेंगे। एलएसी पर अधिकतर अग्रिम मोर्चे इस समय कड़ाके की ठंड की चपेट में हैं और तापमान शून्य से काफी नीचे है। जनरल रावत का बयान ऐसे समय आया है जब एलएसी पर चीन से तनाव बरकरार है।

पूर्वी लद्दाख में चीन से सीमा विवाद के चलते सेना और वायुसेना ने सिक्किम और अरुणाचल समेत एलएसी पर जबर्दस्त मोचेबंदी कर रखी है। नवंबर में सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवाने ने सेना की पूर्वी कमान के तहत विभिन्न ठिकानों का तीन दिवसीय दौरा किया था और उनकी आपरेशनल तैयारियों की समीक्षा की थी। सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कोलकाता में है और उस पर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम सेक्टर में एलएसी की रक्षा करने का दायित्व है।

बीते दिनों सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने इशारों में चीन को कड़ा संदेश देते हुए कहा था कि चीन ने कोरोना के बीच एलएसी के उत्तर-पूर्वी बॉर्डर पर यथास्थिति बदलने की कोशिश की लेकिन हमारे बहादुर जवान अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि भारतीय सशस्त्र बल देश की सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। भारतीय सैन्य बलों के जवान दुनिया की हर चुनौती का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर चुके हैं।